

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 10-12-25



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Wednesday, 10 Dec, 2025

Edition : International Table of Contents

पेज 01 पाठ्यक्रम: जीएस 3: भारतीय अर्थव्यवस्था /	भारतीय चावल पर शुल्क लगाने पर विचार कर रहे हैं ट्रंप इस कदम से अमेरिका पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है
पेज 03 पाठ्यक्रम: जीएस 3 : विज्ञान और तकनीक/प्रारंभिक परीक्षा	आदित्य-एल1 वैश्विक प्रयास में शामिल हो गया है यह खुलासा करते हुए कि 2024 के सौर तूफान ने असामान्य व्यवहार क्यों किया
पेज 04 सिलेबस: प्रीलिम्स	सूर्यकिरण-XIX: उत्तराखंड में भारत-नेपाल सेना का अभ्यास संपन्न
पेज 06 सिलेबस : जीएस 2 : शासन	वर्किंग पेपर कहता है कि एलएलएम के लिए मुफ्त सामग्री पहुंच सुनिश्चित करें
पेज 09 पाठ्यक्रम: जीएस 2: भारतीय राजनीति	विकलांगता के रूप में देखभाल न्याय, मानसिक स्वास्थ्य में गरिमा
पृष्ठ 08 : संपादकीय विश्लेषण पाठ्यक्रम : जीएस 2 : सामाजिक न्याय	विकलांगता के रूप में देखभाल न्याय, मानसिक स्वास्थ्य में गरिमा

पृष्ठ 01 : जीएस 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था

अमेरिका ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी के बाद भारतीय चावल पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का संकेत दिया है, जिसमें उन्होंने भारत और अन्य एशियाई निर्यातकों पर अमेरिकी बाजार में चावल को "डंप" करने का आरोप लगाया था। यह घटनाक्रम नई दिल्ली में निर्धारित अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता से पहले हुआ है। हालांकि इस तरह के उपाय राजनीतिक रूप से संचालित प्रतीत होते हैं, द्विपक्षीय व्यापार डेटा की समीक्षा प्रभाव में एक संभावित विषमता को दर्शाती है, जिसमें अमेरिका को भारत की तुलना में अधिक प्रतिकूल परिणामों का सामना करने की संभावना है।

यह मुद्दा क्यों उठा

- अमेरिकी फार्म लॉबी ने आयातित चावल के बारे में चिंता जताई, जिससे घरेलू कीमतें कम हो गईं।
- राष्ट्रपति ट्रंप ने सवाल किया कि भारतीय चावल को कथित तौर पर टैरिफ छूट क्यों मिलती है और सुझाव दिया कि "टैरिफ इसे जल्दी से हल कर सकते हैं।"
- यह कथन अमेरिकी घरेलू कृषि राहत पैकेज के साथ मेल खाता है - जो चुनावी गणना और लोकलुभावन संकेत का संकेत देता है।

व्यापार डेटा: क्यों टैरिफ अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं अधिक

1. चावल बाजार के रूप में अमेरिका पर भारत की कम निर्भरता

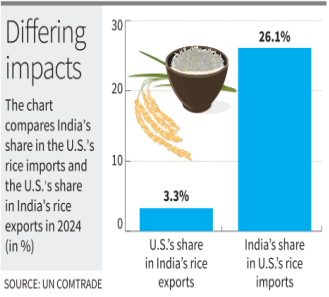
- भारत ने 2023-24 में अमेरिका को 391.74 मिलियन डॉलर मूल्य का चावल निर्यात किया।
- यह भारत के कुल चावल निर्यात का केवल 3.1% है।
- भारत का निर्यात आधार अत्यधिक विविध है और 179 देशों में शिपमेंट जाता है।

2. चावल आयात के लिए भारत पर अमेरिका की उच्च निर्भरता

- अमेरिका ने 2024 में 1.6 बिलियन डॉलर मूल्य के चावल का आयात किया।
- भारत ने कुल अमेरिकी चावल आयात का 26% हिस्सा लिया - जिससे यह एक प्रमुख स्रोत बन गया।
- किसी भी टैरिफ वृद्धि से अमेरिका में चावल की कीमतें बढ़ने की संभावना है, जिससे उपभोक्ताओं और खाद्य प्रोसेसर प्रभावित होंगे।

3. 'डंपिंग' के सीमित साक्ष्य

- भारतीय चावल निर्यात प्रतिस्पर्धी बाजार मूल्य निर्धारण के तहत संचालित होता है, न कि सरकारी सब्सिडी के तहत जो व्यापार को विकृत करता है।
- डंपिंग के आरोप निराधार और राजनीतिक बयानबाजी से अधिक प्रेरित प्रतीत होते हैं।



Trump mulls tariffs on Indian rice; move may affect U.S. more

T.C.A. Sharad Raghavan
NEW DELHI

Days before a U.S. team of negotiators is to visit India to discuss tariffs, U.S. President Donald Trump has hinted at imposing further tariffs on India, this time on rice, to prevent it from "dumping" rice in the U.S.

However, an analysis of trade data between the two countries shows that such tariffs would hurt the U.S. far more than India since only about 3% of India's rice exports go to the U.S., whereas Indian rice makes up more than one-fourth of the quantity imported into the U.S.

In other words, for rice, the U.S. is not a major export destination for India, but India is a major import source for the U.S.

The Hindu had recently reported that a U.S. team of negotiators led by Deputy U.S. Trade Representative Rick Switzer would be in New Delhi on December 10-12 to discuss tariffs with the Indian side. The U.S. has currently imposed a total of 50% tariffs on imports from India.

At a meeting in the White House, when a farmers' representative complained that India, Thailand and other countries were "dumping" rice in the U.S., Mr. Trump asked the U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent: "Why is India allowed to do that? They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice?"

Later, he said the issue can be solved "so quickly with tariffs" on these countries that are "illegally shipping" into the U.S.

Global reach
According to data with the Ministry of Commerce and Industry, India exported rice worth \$391.74 million to the U.S. in 2023-24, which makes up about 3.1% of India's total rice shipments.

India exports rice to 179 other countries.

On the other hand, data from the World Integrated Trade Solutions website shows India accounted for about 26% of the \$1.6 billion worth of rice the U.S. imported in 2024.

"President Trump's threat on December 8 to impose new tariffs on Indian rice, announced alongside a U.S. farm relief package, looks driven more by domestic politics than by trade logic," Ajay Srivastava, founder of think tank Global Trade Research Initiative, and former Director General of Foreign Trade said.

रणनीतिक और आर्थिक निहितार्थ

1. अमेरिका में घरेलू राजनीतिक संकेत

ट्रम्प का बयान किसानों तक पहुंच के उपायों के साथ मेल खाता है।

टैरिफ ग्रामीण मतदाता आधार के अनुकूल संरक्षणवाद की धारणा पैदा करते हैं।

2. द्विपक्षीय व्यापार वार्ता अधिक जटिल हो सकती है

अमेरिका पहले ही विभिन्न भारतीय निर्यातों पर 50% टैरिफ लगा चुका है।

अतिरिक्त कदमों से बाजार पहुंच और टैरिफ युक्तिकरण पर चल रही बातचीत पर दबाव पड़ सकता है।

3. भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था पर सीमित प्रभाव

भारत का चावल निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र वैश्विक है; शिपमेंट को अन्य बाजारों में स्थानांतरित करना संभव है।

इस प्रकार, अमेरिकी टैरिफ का आर्थिक बोझ भारत के लिए नगण्य होगा।

4. अमेरिका में संभावित मूल्य मुद्रास्फीति

कम भारतीय आयात के लिए महंगे आपूर्तिकर्ताओं से सोर्सिंग की आवश्यकता हो सकती है।

यह उपभोक्ता खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है - अमेरिकी प्रशासन के लिए एक अवांछनीय परिणाम।

5. व्यापक संरक्षणवादी रुझानों के लिए संकेत

ट्रम्प के तहत अमेरिका ने ऐतिहासिक रूप से टैरिफ को जबरदस्ती आर्थिक उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किया है।

यहां वृद्धि कई देशों के साथ नए सिरे से व्यापार घर्षण का पूर्वाभास दे सकती है।

समाप्ति

ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय चावल पर शुल्क लगाने की राष्ट्रपति ट्रम्प की धमकी बड़े पैमाने पर जमीनी व्यापार सबूतों के बजाय घरेलू राजनीतिक विचारों से प्रेरित है। अमेरिकी बाजार पर भारत की न्यूनतम निर्भरता और भारतीय चावल आयात पर अमेरिका की महत्वपूर्ण निर्भरता को देखते हुए, इस तरह के टैरिफ की आर्थिक लागत अमेरिकी उपभोक्ता बाजार को असमान रूप से नुकसान पहुंचाएगी। भारत के लिए, इस कदम से उल्लेखनीय व्यापक आर्थिक प्रभाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन चल रही द्विपक्षीय व्यापार वार्ता जटिल हो सकती है। यह प्रकरण एक बार फिर वैश्विक व्यापार नीति में संरक्षणवाद के बढ़ते उपयोग और स्थिर, नियम-आधारित आर्थिक जुड़ाव की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

यूपीएससी प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: व्यापार नीति के संदर्भ में, "डंपिंग" का तात्पर्य है:

- a) घरेलू समर्थन कीमतों से कम कीमतों पर माल का निर्यात करना।
- b) उत्पादन की लागत या बाजार मूल्य से कम कीमतों पर माल का निर्यात करना।
- c) कोटा सीमा से अधिक मात्रा में माल का निर्यात करना।
- d) आयात को प्रतिबंधित करने के लिए टैरिफ लगाना।

उत्तर: b)

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: संयुक्त राज्य अमेरिका में चावल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता होने के बावजूद, अमेरिकी चावल बाजार में भारत का जोखिम कम बना हुआ है। व्यापार निर्भरता में इस विषमता का विश्लेषण करें और भारत के निर्यात लचीलेपन के लिए इसके निहितार्थ की व्याख्या करें। **(150 शब्द)**

पृष्ठ 03 : जीएस 3 : विज्ञान और तकनीक /प्रारंभिक

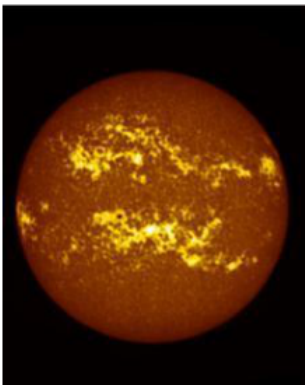
हेलियोफिजिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति में, छह अमेरिकी उपग्रहों के साथ समन्वय में काम कर रही भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य-एल1 ने बताया है कि मई 2024 के सौर तूफान (गैन्नन का तूफान) ने असामान्य रूप से मजबूत व्यवहार क्यों प्रदर्शित किया। अध्ययन में कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) के अंदर एक दुर्लभ चुंबकीय घटना का पता चला, जिससे यह समझने के वैश्विक प्रयासों में काफी तेजी आई कि सौर तूफान कैसे विकसित होते हैं और पृथ्वी के तकनीकी बुनियादी ढांचे को प्रभावित करते हैं। यह उपलब्धि अंतरिक्ष-आधारित अंतरिक्ष-मौसम अनुसंधान में भारत की स्थिति को मजबूत करती है।

Aditya-L1 joins global effort revealing why the 2024 solar storm behaved unusually

The Hindu Bureau
BENGALURU

India's first solar observatory Aditya-L1, along with six U.S. satellites, in a major breakthrough, has revealed why the May 2024 solar storm also known as Gannon's storm behaved so unusually.

The solar storm is composed of a series of giant explosions on the Sun, called coronal mass ejections (CMEs). CMEs are like massive bubbles of hot gas and magnetic energy thrown out from the Sun into space. When these bubbles hit Earth, they can shake our planet's magnetic shield and cause serious trouble for satellites, communication systems, GPS,



The images of the Sun captured by Aditya-L1 during May solar storm, released by the ISRO.

and even power grids.

According to the Indian Space Research Organisation (ISRO), during the May 2024 solar storm, the Sun's magnetic fields, which are like twisted ropes inside a solar storm, were breaking

and rejoining within the storm.

"Usually, a CME carries a twisted "magnetic rope" that interacts with Earth's magnetic shield as it approaches Earth. But this time, two CMEs collided in space and squeezed each other so firmly that the magnetic field lines inside one of them snapped and rejoined in new ways, a process called magnetic reconnection," ISRO said. It added that this sudden reversal of the magnetic field made the storm's impact stronger than expected.

"At the heart of this discovery is India's first solar observatory, Aditya-L1, which joined forces with six U.S. satellites (NASA's Wind, ACE, THEMIS-C,

STEREO-A, MMS, and NASA-NOAA joint mission DSCOVR)," the ISRO said.

"Thanks to precise magnetic field measurements from India's Aditya-L1 mission, scientists were able to map this reconnection region. They found that the area where the CME's magnetic field was tearing and reconnecting was enormous – about 1.3 million km across, i.e., nearly 100 times the size of Earth. It was the first time such a giant magnetic breakup and rejoining had ever been seen inside a CME," it added.

This discovery is expected to enhance the understanding of how solar storms evolve as they travel from the Sun to Earth.

पृष्ठभूमि: 2024 के सौर तूफान को असामान्य किसने बनाया?

सौर तूफान तब आते हैं जब सूर्य चुंबकीय प्लाज्मा की विशाल बूंदों को बाहर निकालता है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) के रूप में जाना जाता है। जब ये सीएमई पृथ्वी से टकराते हैं, तो वे भू-चुंबकीय क्षेत्र को परेशान करते हैं, जिससे खतरा होता है:

उपग्रह संचालन

जीपीएस नेविगेशन

रेडियो संचार

पावर ग्रिड स्थिरता

मई 2024 का तूफान अप्रत्याशित रूप से तीव्र था, जिससे पूर्वानुमानों की तुलना में अधिक मजबूत भू-चुंबकीय गड़बड़ी हुई।

मुख्य खोज: सीएमई के अंदर विशाल चुंबकीय पुनः संयोजन

1. सीएमई-सीएमई टकराव

2024 की घटना के दौरान, दो सीएमई इंटरप्लेनेटरी स्पेस में टकराए, एक दूसरे को संकुचित कर दिए।

इस टक्कर ने उनकी आंतरिक चुंबकीय संरचना को बदल दिया, एक ऐसी घटना जो शायद ही कभी देखी गई हो।

2. चुंबकीय रस्सी व्यवधान

आमतौर पर, एक सीएमई में एक मुड़ी हुई चुंबकीय प्रवाह रस्सी होती है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ बातचीत करती है। इस बार:

चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं टूट गईं और फिर से जुड़ गईं (चुंबकीय पुनः संयोजन)।

चुंबकीय ध्रुवीयता के इस उलटफेर ने पृथ्वी पर तूफान के प्रभाव को तेज कर दिया।

3. पुनः संयोजन क्षेत्र का पैमाना

आदित्य-एल1 के डेटा से पता चला:

पुनः संयोजन क्षेत्र 1.3 मिलियन किमी चौड़ा था, जो पृथ्वी के आकार का लगभग 100 गुना था।

सीएमई के अंदर इतने बड़े पैमाने पर चुंबकीय पुनर्गठन का यह पहला अवलोकन है।

आदित्य-एल1 की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

आदित्य-एल1 ने इनके साथ सहयोग किया:

नासा की हवा, ऐस, एमएमएस, थेमिस-सी, स्टीरियो-ए

डीएससीओवीआर (नासा-एनओएए)

आदित्य-एल1 का योगदान

एमएजी और वीईएलसी जैसे उपकरणों का उपयोग करके सटीक चुंबकीय क्षेत्र माप प्रदान किया।

पुनः कनेक्शन ज़ोन की सटीक मैपिंग सक्षम की गई।

वैश्विक अंतरिक्ष-मौसम निगरानी में भारत का पहला प्रमुख वैज्ञानिक उत्पादन है।

यह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष-मौसम विज्ञान में योगदानकर्ता के रूप में भारत के उदय को उजागर करता है।

खोज का महत्व

1. अंतरिक्ष-मौसम पूर्वानुमान को आगे बढ़ाता है

सीएमई के अंदर चुंबकीय पुनः संयोजन को समझना निम्नलिखित की बेहतर भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है:

तूफान के आगमन का समय

तूफान की ताकत

प्रभाव तीव्रता

यह आधुनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जो उपग्रहों और बिजली नेटवर्क पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

2. भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं को मजबूत करता है

आदित्य-एल1 के वैज्ञानिक लक्ष्यों को मान्य करता है।

सौर खतरों की बहु-एजेंसी निगरानी में भारत की भूमिका को बढ़ाता है।

भारत को हेलियोफिजिक्स अनुसंधान में प्रमुख योगदानकर्ताओं में शामिल करता है।

3. चरम सौर घटनाओं के लिए तैयार होने में मदद करता है

सीएमई-सीएमई युग्मन जैसी दुर्लभ घटनाएं सुपरस्टॉर्म का कारण बन सकती हैं। उनके तंत्र को समझना यह कर सकता है:

प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में सुधार करें

राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करें

विमानन, संचार और रक्षा नेटवर्क की रक्षा करें

4. वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा

परिणाम प्रदर्शित करता है:

अंतरिक्ष-मौसम अनुसंधान की बढ़ती अन्योन्याश्रयता

डेटा साझाकरण का महत्व

एक विश्वसनीय वैज्ञानिक भागीदार के रूप में भारत का उदय

समाप्ति

आदित्य-एल1 मिशन की 2024 गैरन के सौर तूफान के अंदर एक विशाल चुंबकीय पुनः संयोजन की खोज यह समझने में एक सफलता का प्रतीक है कि पृथ्वी की ओर अपनी यात्रा के दौरान सौर तूफान कैसे विकसित होते हैं। असामान्य रूप से मजबूत भू-चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या करके, भारत ने वैश्विक हेलियोफिजिक्स अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अंतरिक्ष-

मौसम प्रणालियों की भविष्य कहनेवाला क्षमता में सुधार किया है। यह उपलब्धि अंतरिक्ष विज्ञान में भारत के बढ़ते नेतृत्व और वैश्विक वैज्ञानिक चुनौतियों में सार्थक योगदान करने की क्षमता को मजबूत करती है।

यूपीएससी प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : चुंबकीय पुनर्संयोजन, हाल ही में एक सीएमई के अंदर देखा गया, संदर्भित करता है:

- A. उच्च तापमान के कारण सौर पवन कणों का विखंडन
- B. चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अचानक टूटने और फिर से जुड़ने से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है
- C. सूर्य की चुंबकीय चक्र गतिविधि में कमी
- D. तीव्र चुंबकीय क्षेत्र के कारण सनस्पॉट का निर्माण

उत्तर : b)

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: चुंबकीय पुनः संयोजन क्या है? 2024 गैसन के तूफान के संदर्भ में सौर तूफानों की तीव्रता को आकार देने में इसकी भूमिका की जांच करें।

पृष्ठ 04 : प्रारंभिक

भारत और नेपाल के बीच वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 19वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। यह अभ्यास दक्षिण एशिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले सैन्य सहयोगों में से एक है और भारत के पड़ोस-पहले दृष्टिकोण और रक्षा कूटनीति का केंद्र है। सूर्यकिरण-XIX ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों में पारस्परिकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया।

SURYAKIRAN-XIX: India-Nepal Army exercise concludes in Uttarakhand

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The India-Nepal joint military exercise, SURYAKIRAN-XIX, concluded at Pithoragarh in Uttarakhand on Tuesday.

Marking the end of the intensive combined training cycle, the Directors-General of Military Operations (DGMOs) of the Indian and Nepal Armies jointly witnessed and validated a two-day battalion-level validation exercise at the Foreign Training Node in Pithoragarh.

The Indian Army said the validation phase showcased joint tactics, techniques and procedures for counter-terrorism operations mandated under



DGMO Lieutenant General Manish Luthra along with DGMO of Nepal Army, Major General Anup Jung Thapa. SPECIAL ARRANGEMENT

Chapter VII of the UN Charter.

The drills featured a suite of cutting-edge technologies, including ISR (intelligence, surveillance, and reconnaissance) and

precision-targeting drones, advanced day/night weapon sights, AI-enabled surveillance feeds, unmanned operational and logistics platforms, and secure battlefield communication

systems. The exercise underscored seamless interoperability, synchronised mission planning and coordinated execution of combined tactical operations in a counter-terrorism environment across battalion, company and small-team levels. Troops carried out intelligence-based surgical missions in complex terrain, employing aerial insertion methods to strengthen rapid-response capability.

Reinforcing ties

As a mark of this enduring partnership, the DGMOs jointly planted a Tree of Friendship, reaffirming the timeless bonds and strategic cooperation between India and Nepal.

सूर्यकिरण-XIX की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

1. उच्च-स्तरीय सत्यापन

दोनों सेनाओं के सैन्य अभियानों के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मनीष लूथरा (भारत) और मेजर जनरल अनूप जंग थापा (नेपाल) ने संयुक्त रूप से दो दिवसीय बटालियन स्तर के सत्यापन अभ्यास की समीक्षा की।

उनकी उपस्थिति भारत-नेपाल रक्षा सहयोग से जुड़े रणनीतिक महत्व और राजनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

2. प्रशिक्षण फोकस: संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत आतंकवाद का मुकाबला

अभ्यास को संयुक्त राष्ट्र अध्याय VII संचालन के आसपास डिजाइन किया गया था, जिसमें जोर दिया गया था:

संयुक्त रणनीति और प्रक्रियाएं

शांति प्रवर्तन

शत्रुतापूर्ण वातावरण में आतंकवाद का मुकाबला

यह संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत और नेपाल की मजबूत भागीदारी के अनुरूप है।

प्रौद्योगिकियों और क्षमताओं का प्रदर्शन

इस अभ्यास में कई उन्नत सैन्य मंच शामिल थे, जो दोनों बलों के आधुनिकीकरण पर प्रकाश डालते थे।

उपयोग की जाने वाली अत्याधुनिक प्रणालियाँ:

आईएसआर प्लेटफॉर्म: खुफिया, निगरानी और टोही

सटीक-लक्ष्यीकरण ड्रोन

उन्नत दिन/रात हथियार जगहें

एआई-सक्षम निगरानी फ्रीड

मानव रहित परिचालन और रसद वाहन

सुरक्षित युद्धक्षेत्र संचार प्रणाली

ये सिस्टम नेटवर्क-केंद्रित युद्ध, स्थितिजन्य जागरूकता और तेजी से प्रतिक्रिया क्षमताओं का समर्थन करते हैं।

प्रचलित परिचालन तकनीकें

खुफिया-आधारित सर्जिकल मिशन

बटालियन, कंपनी और छोटी-टीम स्तरों पर संयुक्त योजना

कठिन इलाके में तेजी से तैनाती के लिए हवाई सम्मिलन के तरीके

संयुक्त सामरिक अभियानों का समन्वित निष्पादन

ये अभ्यास इंटरऑपरेबिलिटी, सामरिक सामंजस्य और मिशन सिंक्रनाइज़ेशन को मजबूत करते हैं।

भारत-नेपाल संबंधों के लिए रणनीतिक महत्व

1. रक्षा कूटनीति को मजबूत करना

सूर्यकिरण दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है।

यह नेपाल के साथ स्थिर और सहयोगात्मक संबंधों को बनाए रखने के भारत के व्यापक रणनीतिक उद्देश्य का समर्थन करता है, विशेष रूप से क्षेत्र में बाहरी प्रभाव के बीच।

2. सीमा सुरक्षा बढ़ाना

भारत और नेपाल एक खुली सीमा साझा करते हैं।

संयुक्त प्रशिक्षण दोनों बलों को प्रबंधित करने में मदद करता है:

सीमा पार आवाजाही

तस्करी नेटवर्क

आतंकवाद से संबंधित खतरे

हिमालयी क्षेत्र में आपदा प्रतिक्रिया सहयोग

3. लोगों से लोगों और रेजिमेंटल संबंधों को मजबूत करना

हजारों गोरखा सैनिक भारतीय सेना में सेवा करते हैं।

संयुक्त अभ्यास इस पारंपरिक बंधन को और गहरा करते हैं।

4. प्रतीकात्मक कूटनीति

दोनों डीजीएमओ द्वारा "दोस्ती का वृक्ष" **लगाना** लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक, सैन्य और सभ्यतागत संबंधों को दर्शाता है।

समाप्ति

अभ्यास सूर्यकिरण-XIX भारत और नेपाल के बीच स्थायी रणनीतिक साझेदारी को प्रदर्शित करता है। आतंकवाद का मुकाबला, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों और उन्नत युद्धक्षेत्र प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करके, यह अभ्यास दोनों सेनाओं की पारस्परिकता और तत्परता को बढ़ाता है। अधिक व्यापक रूप से, यह भारत की पड़ोस-प्रथम नीति को मजबूत करता है, रक्षा कूटनीति को मजबूत करता है, और हिमालय में क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करता है। प्रतीकात्मक "दोस्ती का वृक्ष" दोनों देशों के बीच गहरे और विकसित हो रहे सहयोग की याद दिलाता है।

यूपीएससी प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: व्यायाम सूर्यकिरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत और नेपाल के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
2. 2024 संस्करण संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित था।
3. सूर्यकिरण-XIX का आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में विदेशी प्रशिक्षण नोड में किया गया।
4. केवल भारतीय सेनाएं भाग लेती हैं; नेपाल पर्यवेक्षकों का योगदान देता है लेकिन सैनिकों का नहीं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2 B. केवल 1, 2 और 3 C. केवल 2 और 4 D. केवल 1, 3 और 4

उत्तर : b)

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के तहत एक समिति द्वारा जारी एक वर्किंग पेपर में प्रस्ताव किया गया है कि बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) को प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए सभी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध ऑनलाइन सामग्री तक डिफॉल्ट पहुंच की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रकाशकों को डेटा माइनिंग से बाहर निकलने की अनुमति देने के बजाय, समिति एक कॉपीराइट-सोसाइटी जैसी गैर-लाभकारी संस्था स्थापित करने का सुझाव देती है जो सामग्री निर्माताओं को रॉयल्टी एकत्र और वितरित करेगी। यह सिफारिश प्रकाशकों की कॉपीराइट चिंताओं के साथ एआई में नवाचार को संतुलित करने का प्रयास करती है, ऐसे समय में जब एआई प्रशिक्षण प्रथाओं को मुकदमेबाजी और वैश्विक नियामक अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है।

Ensure free content access for LLMs, says working paper

It says data crawlers for training artificial intelligence models should not be restricted; instead a copyright society should be set up to collect royalties for members and non-members of body

Aroon Deep
NEW DELHI

A government working paper released on Monday suggested that AI large language models (LLMs) such as ChatGPT should, by default, have access to content freely available online, and that publishers should not have an opt-out mechanism for such content.

Instead, a copyright society-like non-profit should be set up to collect royalties for both members and non-members of that body.

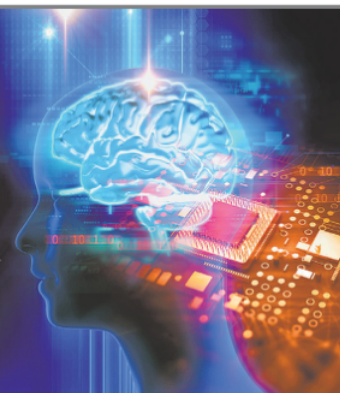
The working paper, authored by a committee formed by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), is not final, and is accepting public comments for 30 days. The document is one of the main indicators of how the Indian government is thinking of balancing copyright holders' fears that AI systems will regurgitate content they invested in without remuneration, and the interests of LLM developers who have routinely consumed massive amounts of data online to train their models.

Nasscom, which was represented in the DPIIT's

LLMs and copyright

A committee formed by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) is accepting public comments on a working paper for 30 days

- The core proposal suggests that LLMs should be allowed to freely access all publicly available online content
- A royalty system has been recommended instead of restrictions
- However, publishers are already concerned about AI regurgitating content. Some are already suing AI firms (e.g., DNPA vs OpenAI)
- There may be pushback from AI firms over the cost burden, while publishers may resist flat royalty distribution



committee, dissented, arguing that forced royalties would amount to a "tax on innovation", and said that "mining" or scraping the Web for data must be allowed for freely available content without paywalls, and that both "crawlable" and access-restricted content providers should have options to "reserve" their content from being mined for LLM development.

Opt-out not feasible

The committee rejected Nasscom's dissent, arguing that small content creators may not have the means to actually enforce such opt-outs.

The Digital News Publishers Association, which represents traditional news media outlets with

a digital presence, including *The Hindu*, has sued ChatGPT maker OpenAI in the Delhi High Court for copyright infringement. OpenAI denies the allegations. The working paper argues that it may not be prudent to await the outcome of this and other similar litigation.

The recommendations, if put in place through a law, will eliminate any allegations of improper access to data, by blessing all access, provided a fee is paid. This model is similar to the "compulsory licensing" framework in place for radio stations in India, which are empowered to play music without negotiating rights for them, as long as a statutorily prescribed fee is paid to the rights holders.

This balancing may face pushback from AI developers and content creators; the former may argue against anything that increases development costs as few AI firms are even profitable at the moment, leaving little appetite to share revenues. Content creators may resist a flat fee if they feel their inputs are more valuable in training a model than those of other royalty recipients.

A payout to the copyright society set up for distributing AI riches to content creators, will be distributed by considering factors such as Web traffic and social indicators, like how respectable a publisher is. Any decision can be taken to the court, the working group says.

वर्किंग पेपर की मुख्य विशेषताएं

1. ऑनलाइन सामग्री तक डिफॉल्ट निःशुल्क पहुंच

एलएलएम (उदाहरण के लिए, चैटजीपीटी) को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वेब सामग्री को क्रॉल या स्क्रेप करने की अनुमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

प्रकाशकों के लिए कोई ऑफ-आउट तंत्र नहीं।

2. रॉयल्टी संग्रह मॉडल

एक गैर-लाभकारी कॉपीराइट सोसायटी करेगी:

एआई डेवलपर्स से रॉयल्टी एकत्र करें।

सदस्यों और गैर-सदस्यों दोनों को भुगतान वितरित करें।

रेडियो प्रसारण में उपयोग किए जाने वाले अनिवार्य लाइसेंसिंग के समान काम करें।

3. नीति प्रेरणा

भारत को एआई नवाचार के लिए एक स्पष्ट और सक्षम नियामक ढांचे की आवश्यकता है।

कॉपीराइट पर मुकदमेबाजी (जैसे DNPA बनाम OpenAI) को नीति की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए।

4. सार्वजनिक परामर्श

पेपर 30 दिनों के लिए टिप्पणियों के लिए खुला है; हितधारकों के इनपुट के बाद अंतिम सिफारिशें तैयार की जा सकती हैं।

असहमति और प्रतिवाद

नैसकॉम की आपत्तियां

जबरन रॉयल्टी भुगतान = "नवाचार पर कर", विकास लागत में वृद्धि।

मुफ्त और भुगतान सामग्री प्रदाताओं दोनों के पास एआई माइनिंग से अपनी सामग्री को "आरक्षित" करने का विकल्प होना चाहिए।

नवाचार-अनुकूल नीति के लिए अनिवार्य शुल्क के बिना मुफ्त सामग्री तक अप्रतिबंधित पहुंच की आवश्यकता होती है।

समिति की प्रतिक्रिया

ऑफ-आउट अव्यावहारिक हैं, खासकर तकनीकी क्षमता की कमी वाले छोटे सामग्री निर्माताओं के लिए।

एक एकीकृत रॉयल्टी तंत्र सुनिश्चित करता है:

निष्पक्षता

प्रशासनिक सादगी

कानूनी स्पष्टता

रॉयल्टी का भुगतान करने पर गैरकानूनी डेटा एक्सेस के भविष्य के दावों को समाप्त करता है।

कानूनी और नियामक संदर्भ

1. चल रही कॉपीराइट मुकदमेबाजी

DNPA (डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन) ने कॉपीराइट उल्लंघन के लिए OpenAI पर मुकदमा दायर किया है। कई वैश्विक प्रकाशकों ने इसी तरह के कानूनी कदम उठाए हैं।

2. अंतर्राष्ट्रीय रुझान

ईयू एआई अधिनियम डेटा माइनिंग की अनुमति देता है जब तक कि सामग्री मालिक बाहर नहीं निकलते हैं।

अमेरिकी न्यायशास्त्र अभी भी विकसित हो रहा है (उचित उपयोग बहस)।

भारत एक बीच के रास्ते की खोज कर रहा है: नियंत्रित पहुंच + मुआवजा।

3. अनिवार्य लाइसेंसिंग सादृश्य

वैधानिक रॉयल्टी का भुगतान करने के बाद भारत में रेडियो स्टेशन किसी भी कॉपीराइट संगीत को चला सकते हैं।

डीपीआईआईटी एआई प्रशिक्षण डेटासेट के लिए एक समान वैधानिक सुरक्षित बंदरगाह का प्रस्ताव करता है।

प्रस्तावित मॉडल के संभावित लाभ

एआई डेवलपर्स के लिए

प्रशिक्षण डेटा तक स्पष्ट कानूनी पहुंच।

कॉपीराइट मुकदमों का जोखिम कम हो गया।

पूर्वानुमानित अनुपालन ढांचा।

सामग्री निर्माताओं के लिए

एआई कंपनियों से रॉयल्टी राजस्व की गारंटी।

उनके काम के अलाभकारी उपयोग से सुरक्षा।

तेजी से बदलते डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में मान्यता का अवसर।

भारत के एआई इकोसिस्टम के लिए

भारत के भीतर एलएलएम विकास को प्रोत्साहित करता है।

विदेशी एआई मॉडल पर निर्भरता कम करता है।

वैश्विक एआई नवाचार केंद्र बनने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

1. एआई डेवलपर्स पर लागत का बोझ

अधिकांश एआई कंपनियाँ अभी तक लाभदायक नहीं हैं।

अनिवार्य रॉयल्टी भुगतान स्टार्टअप को हतोत्साहित कर सकता है।

2. प्रकाशकों के बीच असंतोष

फ्लैट या एल्गोरिथम रॉयल्टी आवंटन योगदान के वास्तविक मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है।

बड़े प्रकाशक एक विभेदित रॉयल्टी संरचना की मांग कर सकते हैं।

3. वितरण की जटिलता

वेब ट्रैफ़िक, प्रकाशक प्रतिष्ठा और सामग्री की मात्रा जैसे मेट्रिक्स का विरोध किया जा सकता है।

विवादों के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, जिससे कार्यान्वयन धीमा हो सकता है।

4. कोई ऑफ-आउट विकल्प नहीं

कुछ निर्माता एआई के लिए अपनी सामग्री के डेटा माइनिंग का मौलिक रूप से विरोध कर सकते हैं।

ऑफ-आउट को खत्म करने से सहमति और स्वायत्तता के बारे में नैतिक चिंताएं बढ़ सकती हैं।

समाप्ति

डीपीआईआईटी वर्किंग पेपर एआई गवर्नेंस के प्रति भारत के दृष्टिकोण को आकार देने में एक साहसिक कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जो नवाचार, कॉपीराइट सुरक्षा और सार्वजनिक हित को संतुलित करने की कोशिश करता है। रॉयल्टी वितरण के साथ एक अनिवार्य-लाइसेंसिंग जैसे मॉडल का प्रस्ताव करके, सरकार का लक्ष्य सामग्री निर्माताओं के लिए समान मुआवजा सुनिश्चित करते हुए एआई डेटा एक्सेस के आसपास अस्पष्टता को खत्म करना है। हालांकि, सिफारिशों को एआई डेवलपर्स (लागत के बोझ पर) और प्रकाशकों (योगदान के अधिक मूल्यांकन) दोनों से मजबूत पुशबैक का सामना करना पड़ सकता है। पॉलिसी की प्रभावशीलता मजबूत हितधारक परामर्श और रॉयल्टी वितरण ढांचे के सावधानीपूर्वक डिजाइन पर निर्भर करेगी।

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न : एलएलएम पर डीपीआईआईटी वर्किंग पेपर एआई नवाचार और कॉपीराइट सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है, लेकिन महत्वपूर्ण नियामक और नैतिक चिंताओं को उठाता है। चर्चा करना। (250 शब्द)

पृष्ठ 09 : शासन 2 : भारतीय राजव्यवस्था

भारत के चुनाव आयोग (ECI) के बिहार जैसे राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2025 करने के निर्णय ने सार्वजनिक बहस और मुकदमेबाजी को जन्म दिया। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह की कवायद से बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित होने का खतरा होता है, जबकि समर्थक इसे चुनावी अखंडता को मजबूत करने के लिए आवश्यक मानते हैं। नायरा जेजीभाय के लेख में बताया गया है कि पहले की कवायदों की तुलना में एक गहन संशोधन संवैधानिक रूप से वैध, प्रशासनिक रूप से आवश्यक और तकनीकी रूप से बेहतर क्यों है।

A deep cleaning of India's electoral rolls

On April 12, 1950, while introducing the Representation of the People Bill in Parliament, the Minister of Law, Dr. B.R. Ambedkar, emphasised that the preparation of an electoral roll is “a condition precedent for election”. The statutory framework in India, therefore, provides for periodic and special revisions to ensure accuracy of the electoral roll.

Nevertheless, there have been concerns about the decision of the Election Commission of India (ECI) to revise the electoral rolls in some States by carrying out a Special Intensive Revision (SIR). The question that arises is whether the ECI's endeavour is ultimately directed at reinforcing or undermining public trust in the democratic process.

Restoring the foundation
There are two modes of updating rolls: intensive revisions, which rebuild the list from scratch, and summary revisions, which make incremental corrections. The last major intensive revision took place between 2002 to 2003. In recent decades, the ECI has relied on special summary revisions, under which claims and objections are invited on a draft roll. In the meantime, rapid migration, expanding urban centres, and high residential mobility have left electoral rolls riddled with duplicates, outdated entries and inaccuracies. Therefore, SIR 2025 was the need of the hour.

The implementation of SIR in Bihar in June 2025 resulted in the filing of several petitions before the Supreme Court labelling the revision exercise unconstitutional and illegal. The challenge proceeds on the basis that insistence on fresh enumeration and documents from existing registered electors is contrary to the constitutional right of universal adult franchise and will result in mass deletion of voters from the rolls. Notably, however, the authority to undertake such an exercise flows directly from the



Naira Jejeebhoy

Advocate whose area of practice includes election law and has represented the Election Commission of India in proceedings



Kumar Utsav

Advocate whose area of practice includes election law and has represented the Election Commission of India in proceedings

The revision and verification of electoral rolls is a routine and necessary process. Such corrections do not, by themselves, imply disenfranchisement or targeting

constitutional scheme itself, which vests the superintendence, direction, and control over the preparation of electoral rolls in the ECI. At the heart of this exercise lies the ECI's endeavour to ensure that only eligible citizens vote, as envisaged under Article 326 of the Constitution. The revision and verification of electoral rolls is a routine and necessary process. Such corrections do not, by themselves, imply disenfranchisement or targeting. Countries such as Germany and Canada rely on civil registries or information sharing between different government agencies to update voter rolls; India does not have such a mechanism. The ECI must therefore independently verify eligibility.

The criticism levelled at SIR 2025 ignores the inherent difficulties in screening citizenship, which is the fundamental basis for eligibility to vote. These difficulties in ascertaining eligibility were, however, anticipated by the Indian legislature, which conferred power on the ECI to carry out a special revision in such manner as it may think fit. SIR 2025 is being carried out pursuant to the constitutional mandate and to ensure that no eligible citizen is excluded from the roll, while simultaneously excluding ineligible persons.

The detailed guidelines for SIR 2025 issued by the ECI contain administrative innovations, technological improvements, and efforts at transparency and participation. Under the present framework of SIR, the ECI has undertaken door-to-door physical verification of each elector. The onus of proving citizenship continues to lie on the applicant. However, the list of acceptable documentary proof is expanded to 11 items, from merely four in 2003, resulting in a more liberal and elector-friendly framework. At the suggestion of the Supreme Court, the ECI also agreed to accept Aadhaar cards as proof of identity. Further, booth-level officers

actively assisted electors in tracing their eligibility and obtaining prescribed eligibility documents.

The SIR process marks a notable shift towards technological accessibility. For the first time, all supporting documents are digitised. Further, enumeration forms are being made available through online platforms. After the publication of the draft roll, any person who has any claim or objections has the option to file the same using the online platform.

The ECI did not restrict capacity-building to its own machinery but also trained booth-level agents of recognised political parties. The SIR guidelines also contain provisions for engagement with parties and sharing of electoral rolls.

What the numbers show

Over 7.5 crore entries were subjected to verification during SIR in Bihar. The total number of electors removed from the draft list was 65 lakh. In addition to the 1,60,813 BLAs of political parties, the Supreme Court also deputed volunteers from the State Legal Services Authority to assist in the submission of claims/objections/corrections online. Nevertheless, only 2,53,524 claims and objections were received in total after publication of the draft roll. Of these, only 36,500 were claims for inclusion (0.56% when compared to the total number of deletions during the revision). Not a single appeal was filed against any deletion. These figures indicate that the SIR exercise was, more or less, grounded in careful and accountable scrutiny.

By embracing SIR, the ECI has demonstrated that its constitutional duties will not be subordinated to convenience or political pressures. Instead, they are being pursued with clarity, courage, and accountability. A democracy strengthens itself not by avoiding difficult tasks, but by undertaking them when it matters most. SIR 2025 is one such effort.

पृष्ठभूमि: मतदाता सूची संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने जनप्रतिनिधित्व विधेयक (1950) पेश करते हुए कहा कि सटीक मतदाता सूची चुनाव के लिए एक पूर्व शर्त है।

भारत के वैधानिक ढांचे में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

गहन संशोधन (रोल का पूर्ण पुनर्निर्माण)।

सारांश संशोधन (वृद्धिशील सुधार)।

अंतिम प्रमुख गहन संशोधन 2002-03 में हुआ था। तब से, तेजी से शहरीकरण, प्रवासन और गतिशीलता के परिणामस्वरूप डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ, पुराने पते और अशुद्धियाँ हुई हैं, जिससे एक गहरी सफाई प्रक्रिया की आवश्यकता है।

एसआईआर 2025: संवैधानिक और कानूनी औचित्य

1. संवैधानिक आधार

अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित करता है।

संशोधन का उद्देश्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (अनुच्छेद 326) को यह सुनिश्चित करना है:

पात्र मतदाता शामिल हैं, और

अयोग्य मतदाताओं को हटा दिया जाता है।

2. सर्वोच्च न्यायालय की चुनौतियाँ

बिहार में याचिकाओं में तर्क दिया गया:

नए सत्यापन से मौजूदा मतदाताओं पर बोझ पड़ता है।

गैरकानूनी विलोपन का जोखिम।

लेख काउंटर करता है कि:

संशोधन का मतलब स्वचालित रूप से मताधिकार से वंचित करना नहीं है।

मजबूत लोकतंत्र वाले देश (जर्मनी, कनाडा) नागरिक रजिस्ट्रियों का उपयोग करके रोल अपडेट करते हैं - भारत में ऐसी प्रणालियों का अभाव है और उन्हें ईसीआई के नेतृत्व वाले सत्यापन पर भरोसा करना चाहिए।

एसआईआर 2025 क्यों आवश्यक हो गया

उच्च गतिशीलता और शहरी प्रवासन सारांश संशोधनों को अपर्याप्त बनाते हैं।

चुनावी धोखाधड़ी की चिंताएं (डुप्लिकेट, मृत मतदाता, गलत पते)।

एक साफ सूची वैधता को मजबूत करती है और चुनाव लड़ने से रोकती है।

एसआईआर 2025 में प्रशासनिक और तकनीकी सुधार

1. डोर-टू-डोर सत्यापन

प्रत्येक मतदाता ने शारीरिक रूप से सत्यापित किया - महत्वपूर्ण पैमाने और कठोरता।

2. विस्तारित दस्तावेजी प्रमाण

4 दस्तावेजों (2003) से लेकर आज 11 स्वीकार्य दस्तावेजों तक ।

सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों के बाद आधार को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया।

3. प्रौद्योगिकी एकीकरण

सभी सहायक दस्तावेजों का डिजिटलीकरण।

गणना प्रपत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता।

मसौदा प्रकाशन के बाद दावे और आपत्तियां ऑनलाइन दायर की जा सकती हैं।

4. राजनीतिक दल की भागीदारी

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंटों (बीएलए) को प्रशिक्षित किया गया था।

बहु-पक्षीय जांच सुनिश्चित करने के लिए रोल्स ने पारदर्शी रूप से साझा किया।

5. नागरिक समाज की भागीदारी

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्वयंसेवकों ने सुधार दाखिल करने में मतदाताओं की सहायता की।

बिहार के एसआईआर 2025 के परिणाम

1. बड़े पैमाने पर सफाई

7.5 करोड़ प्रविष्टियों का सत्यापन किया गया।

65 लाख हटाए गए (केवल अपात्र/डुप्लीकेट प्रविष्टियां)।

2. न्यूनतम विवाद या सार्वजनिक प्रतिरोध

केवल 2.53 लाख दावे/आपत्तियां प्रस्तुत की गईं।

नए समावेशन के लिए केवल 36,500 दावे

यह कुल विलोपन का 0.56% है, जो मनमाने ढंग से हटाने के बजाय सटीकता का सुझाव देता है।

हटाने के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई।

विवादों की कम संख्या इंगित करती है कि अभ्यास काफी हद तक सटीक, व्यवस्थित और पारदर्शी था।

चुनावी लोकतंत्र के लिए बड़े निहितार्थ

मतदाता सूची की अखंडता को मजबूत करता है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की नींव है।

राजनीतिक दबावों के बावजूद चुनौतीपूर्ण सुधार करने की ईसीआई की इच्छा को प्रदर्शित करता है

भारत मतदाता सूची के रखरखाव में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के करीब पहुंचा।

यह दर्शाता है कि लोकतांत्रिक विश्वसनीयता के लिए सक्रिय, समय पर सुधार की आवश्यकता होती है, न कि प्रशासनिक जड़ता की।

समाप्ति

लेख में तर्क दिया गया है कि विशेष गहन संशोधन (एसआईआर 2025) मतदाता सूची प्रबंधन में संवैधानिक जिम्मेदारी, सटीकता और पारदर्शिता के प्रति ईसीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्वास को कम करने के बजाय, यह पहल अशुद्धियों को दूर करके और केवल योग्य नागरिकों को वोट देने के लिए सुनिश्चित करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने का प्रयास करती है। जैसे-जैसे लोकतंत्र जटिल चुनौतियों का सामना करके और उनसे बचकर खुद को मजबूत करते हैं, एसआईआर 2025 भारत की चुनावी नींव की अखंडता की रक्षा के लिए एक आवश्यक और साहसिक कदम के रूप में खड़ा है।

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न : गंभीर रूप से जांच करें कि क्या विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) 2025 जैसे बड़े पैमाने पर मतदाता सूची संशोधन भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को मजबूत या कमजोर करते हैं। **(150 शब्द)**

Care as disability justice, dignity in mental health

A 60-year-old recalls eating leftovers as a child, in the absence of his birth family, and, even today, is passively engaged with life. A survivor of childhood abuse says that she now views her problems as 'thoosi' (dust), but only after being homeless and battling insurmountable trauma. Then there is a recollection by someone of stark abuse while under psychiatric care, who was chained and forced to drink water from a washroom because they were deemed 'unmanageable'.

These stories embody suffering in ways that numerical data fail to capture. These are stories that spotlight how different people are impacted and respond differently to distress and care, based on their contexts and beliefs. A lack of commitment to unpack these narratives risks shrinking the immersive exploration that is warranted. It may touch the surface of healing and venture a little beyond but will ultimately relegate the discourse that spotlights barriers, attitudes, social distances, and inadequate care systems to the margins.

Yet, dominant approaches to psychosocial disability continue to view these experiences through a deficits lens, as they are focused on 'integration' into communities that hold stereotypical understandings of productive living, a reductionist imagination of 'the normal', and a social order that goes unquestioned. The gaps in mental health-care access continue to range from 70%-90% globally. While third generation medications promise fewer side-effects and evidence-based therapies proliferate, the fundamental questions remain.

The gaps

We argue that mental health care must be radically reimagined as the primary pursuit of dignity and disability justice that centres equity, inclusion, and diversity, highlighting complexities with all their nuances; as the practice of staying with people and persisting alongside them through suffering, whether that suffering is relational, material, or structural in nature. Care in this lens is a process of individual-level meaning-making, responding to adverse life events, relational disruptions and existential queries, while fulfilling needs for safety, relationships, everyday wins, and problem-solving. It is also a tussle between one's context and one's chosen path, complicating the narrative and the care plan.

To untangle the knots between mental health and the social context we must start with asking what kind of world creates such suffering, and how can one standardise essential protocols while achieving personalisation at scale.

Sustained material and relational deprivation,



Vandana Gopikumar
is with The Banyan and Banyan Academy of Leadership in Mental Health and is a mental health and social care practitioner and care systems researcher



Lakshmi Narasimhan
is with The Banyan and Banyan Academy of Leadership in Mental Health, and is a mental health and social care practitioner and care systems researcher

Mental health care must be radically reimagined as the primary pursuit of dignity and disability justice that gives importance to equity, inclusion and diversity

both as a cause and an outcome of mental ill health, often go unaddressed, resulting in a range of losses. An example is found in the National Crime Records Bureau (NCRB) data on suicides, which while reducing causes to monotonic categories as reported by police, shows that a third of suicides in India are due to family problems and another tenth due to relational ruptures. Feelings of shame, rejection, alienation and abandonment that underlie distress are rarely spoken about, limiting both the language and expression of psychic pain. Solutions often attempt to fix patterns (labelled 'maladaptive'), placing the onus for broken relationships, social withdrawal and loss of vitality squarely on the person.

Multiple explanations for distress may persist concurrently, ranging from biological (neurotransmitter alterations, inflammatory markers), psychological (learned patterns, cognitive frameworks), social (isolation, economic precarity, discrimination), cultural (loss of traditional meaning systems), political (oppressive structures, dismantled safety nets), and historical (intergenerational trauma, colonial legacies). These explanations do not exist in isolation. They are overlapping and intersect with caste, class, gender and queer identities in ways that shape both the experience of suffering and access to care. Rather than viewing these as competing frameworks, comprehensive care requires attention to diverse explanations and approaches simultaneously.

On care practice

People experiencing emotional and social crises or intense alienation require the space to grapple with these existential uncertainties. In contrast, dominant notions that locate these within biological or social determinants frameworks obscure these meaning-making dimensions of mental well-being. As much as living in extreme housing precarity may limit opportunities to pursue what is personally meaningful, having a stable house or income alone cannot diminish feelings of disconnection from self and the world.

While privileging tangible interventions such as medication, housing or cash transfers and grit and resilience building (which is not exclusively individual dependent) must assume greater importance, equally, care planning must highlight the need for relational work that engages with questions around vulnerabilities and invulnerabilities, purpose and existential incoherence, located in social-ecological contexts. In these ideas lie the foundations of disability justice, that embodies the spirit of liberation and wholeness, and not mere integration into an unequal world.

What if we thought critically, practised with solidarity, and pursued more longitudinal work that is real-world sensitive? Care would then be re-centred as the practice of relational justice and examine concerns that sustain distress and approaches that suffuse hope in complex scenarios. This could range from medications and economic security, to finding hope in spiritual practice, one's goals and community connection. The focus shifts from treatment to 'what does this person need to live the life they want?', recognising that there are variegated and yet valid ways of understanding and responding to distress.

A secondary yet important gain might address the one issue that affects all mental health work – engagement with a service and continuity of care. Many people who access a service are disillusioned and lose faith and trust for innumerable reasons. This disengagement could often result in a downward spiral into states of despair, loneliness and homelessness. Building trust involves honest collaborations, dialogic practice and acceptance of non-linear outcomes.

Justice beyond fair distribution of resources or services, as espoused by Sandel, becomes central; as a process of recognising what we owe to one another and the moral threads holding our relationships and society. In mental health care, this means asking whether our systems centre dignity and account for the injustices that precipitated suffering, and, importantly, whether care can even be conceived without addressing the contexts that created harm in the first place.

Transforming care, education and research

Mental health education may need to prepare people to sit with discomfort and uncertainty, navigate the complexity of a person's social world, celebrate small wins, and remain open to diverse approaches. Research priorities require reorientation toward capturing the granular aspects of care rather than only large-scale, generalisable findings. These actions require examining micro-level processes through implementation science and transdisciplinary methods that link practice and theory, enabling continuous learning about what works, for whom, and how.

Most critically, those currently designated as non-specialists and those who bring lived experience need to be recognised and compensated as practitioners who bring community wisdom and contextual understanding that formal training cannot replicate, and receiving preparation and resources that enable them to engage with the same systemic support afforded to those with professional credentials.

जीएस - 2 : सामाजिक न्याय

यूपीएससी मुख्य अभ्यास प्रश्न : गंभीर रूप से जांच करें कि गरीबी, जाति, लिंग, आवास अनिश्चितता और अंतर-पीढ़ीगत आघात जैसे सामाजिक निर्धारक मानसिक स्वास्थ्य परिणामों को कैसे आकार देते हैं। भारत की मानसिक स्वास्थ्य नीति को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? (250 शब्द)

संदर्भ:

लेख में बायोमेडिकल न्यूनीकरणवाद के बजाय गरिमा, विकलांगता न्याय और प्रासंगिक देखभाल को केंद्रित करके भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की मौलिक पुनर्कल्पना के लिए तर्क दिया गया है। आघात, बेघर होने और प्रणालीगत उपेक्षा के जीवित अनुभवों से आकर्षित होकर, लेखक इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे प्रमुख मानसिक-स्वास्थ्य ढांचे पीड़ा की सामाजिक, संबंधपरक और संरचनात्मक जड़ों को संबोधित करने में विफल रहते हैं। यह टुकड़ा एक अधिक न्यायसंगत, व्यक्ति-केंद्रित और सामाजिक रूप से जागरूक मानसिक-स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र की मांग करता है।

प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया**1. जीवित अनुभव अदृश्य पीड़ा को प्रकट करते हैं**

की कथाएँ:

बचपन की उपेक्षा,

चोट

मनोरोग संस्थानों के भीतर दुर्व्यवहार,

बेघरता,

संकट के ऐसे रूपों को प्रदर्शित करें जिन्हें अकेले आँकड़े नहीं पकड़ सकते। इन कहानियों से पता चलता है कि पीड़ा भौतिक अभाव, सामाजिक कलंक और संरचनात्मक बहिष्कार से आकार लेती है, न कि केवल नैदानिक लक्षणों से।

2. प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण घाटे उन्मुख रहते हैं

वर्तमान मनोसामाजिक विकलांगता ढांचे:

व्यक्तियों को एक संकीर्ण रूप से परिभाषित सामान्य में "एकीकृत" करने पर ध्यान केंद्रित करें;

उत्पादकता और व्यवहार सुधार पर जोर देना;

अक्सर संकट के सामाजिक-सांस्कृतिक अर्थों को नजरअंदाज कर देते हैं;

कमजोरियों को आकार देने वाले संरचनात्मक अन्यायों पर ध्यान न दें।

उपचार का अंतर - वैश्विक स्तर पर 70-90% - दवा और उपचारों में प्रगति के बावजूद बना हुआ है।

एक नए ढांचे की आवश्यकता क्यों है**1. गरिमा और विकलांगता न्याय के प्रश्न के रूप में मानसिक स्वास्थ्य**

लेख एक प्रतिमान के लिए तर्क देता है जहां:

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल इच्छिणी, समावेश, विविधता को बनाए रखती है;

संकट को जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक चश्मे के माध्यम से एक साथ समझा जाता है;

ध्यान न केवल लक्षणों में कमी पर है, बल्कि अर्थ, संबंधपरक समर्थन और संरचनात्मक परिवर्तन के साथ जीने पर है।

यह UNCRPD (विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन) अधिकार-आधारित ढांचे के अनुरूप है।

2. सामाजिक निर्धारकों और प्रासंगिक पीड़ा को संबोधित करना

लेख पर प्रकाश डाला गया है:

निरंतर गरीबी,
संबंधपरक अभाव,
शर्म और अलगाव,
जाति, वर्ग, लिंग और समलैंगिक पहचान-आधारित हाशिए पर,
अंतरपीढ़ीगत आघात और औपनिवेशिक विरासत।

ये निर्धारक संकट और देखभाल तक पहुंच दोनों को आकार देते हैं। वर्तमान प्रणालियाँ अक्सर उन संदर्भों की जांच किए बिना व्यक्तियों को विकृत करती हैं जो नुकसान पैदा करते हैं।

3. संकट के कई स्पष्टीकरण सह-अस्तित्व में होने चाहिए

एक मॉडल (जैविक बनाम मनोसामाजिक) को विशेषाधिकार देने के बजाय, लेख बहुलवाद पर जोर देता है:

न्यूरोट्रांसमीटर परिवर्तन,
सीखा पैटर्न,
आर्थिक अनिश्चितता,
सांस्कृतिक अर्थ प्रणाली,
राजनीतिक उत्पीड़न,
ऐतिहासिक आघात

देखभाल योजना में सभी पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए।

देखभाल प्रथाओं को बदलना

1. संबंधपरक न्याय के रूप में देखभाल

देखभाल की पुनर्कल्पना करने के लिए आवश्यक है:

व्यक्तियों के साथ एकजुटता और दीर्घकालिक जुड़ाव;
अस्तित्वगत प्रश्नों, अर्थ-निर्माण और व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए जगह बनाना;
"उपचार अनुपालन" से "इस व्यक्ति को वह जीवन जीने के लिए क्या चाहिए जो वह चाहता है?" पर ध्यान केंद्रित करना।
यह दृष्टिकोण देखभाल की निरंतरता का समर्थन करता है और विघटन को कम करता है।

2. मूर्त हस्तक्षेप से परे

जबकि दवा, आवास और नकद हस्तांतरण महत्वपूर्ण हैं, उनके साथ होना चाहिए:

संबंधपरक कार्य,
संवाद जुड़ाव,
विश्वास निर्माण,
गैर-रैखिक वसूली की स्वीकृति।

यह मॉडल मानसिक स्वास्थ्य संकटों को मानवीय अनुभवों के रूप में देखता है, न कि केवल नैदानिक घटनाओं के रूप में।

3. सामाजिक संबंधों की मरम्मत के रूप में न्याय

माइकल सैंडल की न्याय की अवधारणा पर आकर्षित, लेख का तर्क है कि मानसिक स्वास्थ्य प्रणालियों को चाहिए:

पहचानें कि समाज व्यक्तियों के प्रति क्या ऋणी है,
उन अन्यायों को दूर करें जो संकट को जन्म देते हैं,
देखभाल प्रदान करें जो उत्पीड़न की जीवित वास्तविकताओं पर विचार करती है।

शिक्षा और अनुसंधान को बदलना

1. मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सकों को अलग तरह से प्रशिक्षण देना

शिक्षा को पेशेवरों को इसके लिए तैयार करना चाहिए:

अस्पष्टता और बेचैनी के साथ बैठो,
जटिल सामाजिक दुनिया को समझें,
छोटी जीत को महत्व दें,
विविध और प्रासंगिक दृष्टिकोण अपनाएं।

2. अनुसंधान को सूक्ष्म-स्तरीय देखभाल प्रक्रियाओं को पकड़ना चाहिए

लेख इसके लिए वकालत करता है:

कार्यान्वयन विज्ञान,
ट्रांसडिसिप्लिनरी तरीके,
वास्तविक दुनिया की संवेदनशीलता,
सीखना "क्या काम करता है, किसके लिए और कैसे।

3. गैर-विशेषज्ञ और जीवित-अनुभव चिकित्सकों को पहचानना

जीवित अनुभव वाले लोग और सामुदायिक कार्यकर्ता होने चाहिए:

वैध चिकित्सकों के रूप में मान्यता प्राप्त,
उचित मुआवजा दिया गया,
प्रणालीगत सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया।

यह पेशेवर विशेषज्ञता के सख्त पदानुक्रम को चुनौती देता है।

समाप्ति

लेख मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के एक आमूल-चूल परिवर्तन के लिए कहता है: एक ऐसी प्रणाली से जो व्यक्तियों को विकृत करती है जो सामाजिक, संबंधपरक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक संदर्भों में निहित संकट को पहचानती है। गरिमा, विकलांगता न्याय, संबंधपरक देखभाल और प्रासंगिक समझ को अग्रभूमि देकर, भारत मानसिक स्वास्थ्य प्रणालियों की ओर बढ़ सकता है जो मानवीय, समावेशी और वास्तविक दुनिया की जटिलता के प्रति उत्तरदायी हैं। इस तरह का बदलाव उपचार के अंतर को पाटने और एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक है जहां लोग न केवल जीवित रहते हैं, बल्कि सार्थक, जुड़ा हुआ जीवन जीते हैं।